



भारत-रूस : S-400 डील के निहितार्थ

प्रदीप मौर्य

शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

ABSTRACT :

भारत और रूस के सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मिसाल है। जहाँ रूस अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है; वहीं भारत ने अपनी समन्वयकारी क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत की आजादी से लेकर, शीत युद्ध एवं सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत एवं रूस के सम्बन्ध प्रगाढ़ ही रहे हैं। 21वीं सदी में उनके द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के मध्य, रक्षा, आन्तरिक, व्यापार, पर्यटन, कृषि, संचार, चिकित्सा जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोनों देशों की निकटता परिलक्षित होती है।

गोवा के 17वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का रूसी भाषा में कहा गया वक्तव्य – (1) 'स्तारीय दुग लुछे नोविख दुख' (यानी एक पुराना मित्र, दो नए मित्रों से बेहतर होता है)। (2) 'इंडियाई रस्सीया- रूका अब रूकु व स्वेतलोय बद्दुशीव' (यानी भारत और रूस उज्ज्वल भविष्य के लिए एक साथ हैं)।

हाल ही में सम्पन्न S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेन्स सिस्टम पर हुई डील उक्त बातों को प्रमाणित भी करती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आ रही हैं, जिनका दायरा अभी तो अमेरिका तक ही सीमित है; लेकिन आगे चलकर एशिया में चीन, पाकिस्तान एवं यूरोप की तरफ से भी ऐसी चुनौतियाँ प्रकट हो सकती हैं। प्रस्तुत आलेख में इसी विषय पर विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना –

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आये और उन्होंने भारत-रूस '19वें वार्षिक सम्मेलन' में संयुक्त वार्ता के साथ कुछ संधियों के माध्यम से भारत और रूस को निकट लाने में जो उत्साह दिखाया, जिससे वैश्विक राजनीति में सकारात्मक सम्बन्धों की मजबूती दिखाई देती है। पुतिन की यात्रा के दौरान सम्पन्न हुए संयुक्त वार्ता के साथ ही भारत और रूस के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। जिसमें उर्जा, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेन्स पर हुई डील रही है। भारत इस डील के लिए लम्बे समय से प्रयासरत रहा है।

भारत की लम्बी सीमा रेखा है जिसके दो प्रमुख पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से चुनौतियाँ मिलती हैं एवं इस डील के सम्पन्न हो जाने से भारत की सीमा सुरक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी साथ ही वायु सेना का मनोबल भी बढ़ेगा एवं भारत एयर डिफेन्स तकनीक में आत्मनिर्भर होगा। लेकिन दूसरी तरफ S-400 की डील ने भारत को चर्चा के केन्द्र बिन्दु में ला दिया है एक तरफ भारत की रक्षा श्रेणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही दूसरी तरफ अमेरिका का 'काटसा एक्ट' एवं चीन तथा मध्य एशिया के सम्बन्ध भारत के प्रति क्या होंगे।

क्या है S-400 ? -



1. S-400 ट्रायम्फ एयर मिसाइल डिफेन्स सिस्टम लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। जिसे नाटो SA-21 ग्रॉलर के नाम से रिपोर्ट करता है।
2. S-400 हवा में सभी प्रकार के टारगेट्स, जिसमें एयरक्राफ्ट, UAV (Unnamed vehicle Arial vehicle) तथा बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं, को 400 किमी० की रेंज और 30 किमी० की ऊँचाई तक निशाना बना सकता है, यह एक साथ 36 टारगेट्स को निशाने पर ले सकता है और 1000 किमी० की दूरी पर आब्जेक्ट को पकड़ सकता है।
3. 40,000 करोड़ रु० डील S-400 की उपयोगिता को रेखांकित करती है, यह S-300 का उन्नत संस्करण है जिसका इस्तेमाल इस समय चीन की सेना भी कर रही है लेकिन अमेरिकी वायु सेना अभी तक इसकी काट ढूँढ पाने में असफल रही है।
4. एस-400 के भारत की रक्षा श्रेणी में शामिल हो जाने से भारत की रक्षा क्षमता में आमूल परिवर्तन आयेगा जो चीन तथा पाकिस्तान की संयुक्त गतिविधियों पर नजर रखेगी।



क्र.सं.	देश	सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल
1.	चीन	TY, HQ series, Sky Dragon, QW series etc
2.	फ्रांस	Masura, AS-20, Roland etc
3.	जर्मनी	Roland, IDAS and LFK NG
4.	भारत	Akash, QRSAM, Brak 8, Trishul Pradyumna, Ashwin and PDV Ballistic Missile Interceptor
5.	इजराइल	Arrow, Barak and SPYDER
6.	पाकिस्तान	Anza
7.	अमेरिका	FIM, MIM, CIM, RIM, Series and Terminal High Altitude Area Defence (THAAD)
8.	रूस	2K, Series, 9K series, S-200, S-300, S-400 and S-500
9.	नार्थ कोरिया	KN6

● नई दिल्ली-मास्को की नजदीकियाँ एवं काटसा कानून -

S-400 डील के सम्पन्न होने के बाद से ही पश्चिम और पूर्व दो गुटों में बँटता दिख रहा है। अमेरिका ने इस डील के बाद यह घोषणा की वह भारत को देख लेगा अर्थात् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 नवम्बर 2018 को खुद यह धमकी दी। यह चेतावनी एक सम्प्रभु देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है इसको कितना नैतिक कहा जाय अभी विचारणीय है।

भारत-रूस के सम्बन्ध ने "बीजिंग-मॉस्को-इस्लामाबाद" त्रिकोण को यह आश्वस्त किया कि रूस इस त्रिकोण में शामिल जरूर है लेकिन नई दिल्ली की प्रभावशीलता में कोई कमी नहीं होगी।

भारत ने तत्कालीन, सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त, 1971 को 'ट्रीटी ऑफ पीस' क्रेडिशिप एण्ड को - ऑपरेशन' पर हस्ताक्षर किए थे और वह भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के साथ खड़ा हुआ था। (एक प्रकार से अमेरिका के खिलाफ) इस दृष्टि से 1971 की भारत विजय में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग को भुलाया नहीं जाना चाहिए जिसने 1962 में धुमिल हुई भारतीय प्रतिष्ठा को बहुत हद तक पुनः स्थापित करने में मदद की थी।

- रूस ने 42 सुपर सुखोई - 30 MKI लडाकू विमान भारत को मुहैया करवाने के लए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है।
- रूस के साथ कामोव- 226 हैजीकॉप्टर बनाने सम्बन्धी जो समझौता हुआ है, वह मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ी रक्षा परियोजना है।
- भारत रूस के साथ ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का सदस्य है, और रूस भारत को सुरक्षा परिषद परिषद में स्थायी सीट व NSG में शामिल करने का समर्थन करता है।
- भारत में छह परमाणु बिजली परियोजना में मदद करने के अलावा रूस ने 2022 में भेजने जाने वाले अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करने पर भी सहमति दी है।

भारतीय रक्षा प्रणाली की प्रमुख सामग्री का आयात रूस से ही होता है। एवं सैन्य हथियार का प्रमुख आयातक देश भारत है। जो सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही आयात करता है। 2012-16 के दौरान रूस भारत को हथियार निर्यात करने वाला अग्रणी देश था।



• अमेरिका का काटसा कानून एवं S-400 डील -

अमेरिका का एक एक्ट है - काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थू सैंक्शंस एक्ट (काटसा)। इसका सेक्शन 231 ट्रांजैक्शन बार्ड-ट्रांजैक्शन बेसिस पर विचार करता है जिसके अनुसार रूस के साथ किसी भी देश के स्ट्रैटेजिक रक्षा सम्बन्धी लेन-देन पर रोक लग जाती है।

- इस कानून को अमेरिकी संसद ने रूस, ईरान, उत्तर कोरिया को ध्यान में रखकर बनाया है लेकिन भारत भी इसकी परिधि में आ गया। इस एक्ट के तहत अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है जो रूस के रक्षा और खुफिया संस्थानों के साथ लेन-देन में शामिल
- भारत के तीनों सेनाओं की वस्तु सूची का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही प्राप्त होता है; जिसमें टैंक, लडाकू विमान, पनडुब्बियाँ और आधुनिक विध्वंसक हथियार शामिल है, अगर भारत काटसा एक्ट को मान्यता देता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत की सम्प्रभुता पर पड़ेगा एवं भारत की रक्षा प्रणाली कमजोर होगी जो कहीं से भी भारत के हित में नहीं है।
- बीजिंग-इस्लामाबाद के बीच की बढ़ती मित्रता ने इस डील को और भी मजबूती दी है, जिससे भारत अपनी सीमा सुरक्षा की रक्षा कर सके।

➤ अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रहे ईरान को भी आर्थिक प्रतिबन्धों की धमकी दी गयी है, जहाँ भारत के चाबहार बन्दरगाह को विकसित किया जा रहा है। भारत-रूस के प्रगाढ़ होते सम्बन्धों ने यह तय कर दिया है कि 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति ही एकमात्र विकल्प नहीं है।

हाल ही में सम्पन्न भारत-अमेरिका '2 प्लस 2' वार्ता के दौरान अमेरिका की तरफ से कहीं भी यह संकेत नहीं मिला है कि भारत-रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम न खरीदे।

● S-400 की उपयोगिता भारतीय सीमा सुरक्षा के सन्दर्भ में –

➤ S-400 की रक्षा प्रणाली ने भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान की है जिससे भूमि व हवा दोनों पर भारतीय प्रभुत्व स्थापित होगा।

➤ भारत की लगभग 4000 किमी० लम्बी सीमा चीन के साथ है जहाँ भारत को अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में S-400 मिसाइल प्रणाली की आवश्यकता थी जिससे भारत-रूस समझौते ने सम्भव बना दिया।

➤ S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद से भारत को सीमा पर से होने वाले परमाणु खतरे से सुरक्षा प्राप्त होगी एवं पाकिस्तान व चीन की परमाणु नियोजित धमकियों के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।

इस समझौते के सन्दर्भ में एक तथ्यात्मक सन्दर्भ ये है कि भारतीय रक्षा प्रणाली पाकिस्तान के वायु चौकियों की निगरानी भी कर सकता है एवं अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रेरित आंतकवादी क्रियाकलापों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा।

निष्कर्ष –

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-रूस में सम्बन्ध काफी प्रगाढ़ है, जिसके परिणाम स्वरूप S-400 डील हुयी है। पूरे विश्व राजनीति में जहाँ शस्त्र निःशस्त्रीकरण की बात हो रही हो वही हथियारों की दौड़ यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये नैतिक रूप से सही है। एक सम्प्रभु देश होने के नाते भारत को अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना प्राथमिक उद्देश्य है। भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन परमाणु सम्पन्न राष्ट्र है जिससे भारत की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ अमेरिका का 'काटसा कानून' इस दिशा की ओर इंगित करता है कि यह डील नहीं होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यही विशेषता यहाँ दृष्टिकोणीय है।

21वीं सदी परमाणु युग की सदी है जिसमें परमाणु सम्पन्न देश ही वैश्विक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि, भारत-रूस के बीच हुए S-400 समझौते ने एक नई मित्रता को जन्म दिया है। यह डील दोनों राष्ट्रों के बीच मील का पत्थर साबित होगी।

सन्दर्भ सूची –

- 1- India Russia S-400 Missile deal : *All you need to know*, Times of India : Oct 5, 2018
- 2- Roy Shubhajit, "Explained : what S-400 air defence system deal with Russia Means to India" The Indian express, october 4, 2018 New Delhi.
- 3- S-400 can launch 72 Missiles Simultaneously engage 36 targets at a time : *Economictimes.com* Oct. 11, 2018.
- 4- Ashley J. Tellis : How can U India Relations Survive the 400 deal? "*Carnegie Endowment for International peace*" August 29, 2018.
- 5- Abhijit Iyer-Mitra : "*What Makes S-400 a Politically sawy deal, but hardly a game Changer*" Business standard, Oct, 4, 2018.
- 6- India - Russia defence deal : *S-400 air defence system can Launch 72 missiles, engage 36 targets at on go*. Hintustantimes.com, Oct 6, 2018.